The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 2 | February 2024
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : महत्व व चुनौतियां

गंगा सिंह *

असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हल्द्वानी उत्तराखंड

नंदन सिंह

शोध छात्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड

nbasera143@gmail.com

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords :

शिक्षानीति, चुनौती, महत्व, उत्तराखंड, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, विद्यालय, विविधता, शिक्षा प्रणाली, बच्चे

ABSTRACT

उत्तराखंड अपने आप में प्राकृतिक विविधताओं वाला राज्य है जहां कहीं अति दुर्गम पर्वतीय जिले हैं तो कहीं मैदानी क्षेत्र है इसी कारण किसी भी नीति का निर्धारण करते समय यहां की विभिन्नता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उसका सिंह धामी द्वारा शिक्षा निदेशालय में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ बाल वाटिका से किया गया सरकार का दावा है कि ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रदेश के सभी ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों में "बाल वाटिका" की कक्षाएं शुरू कर दी गई है निजी विद्यालयों में नर्सरी से होने वाली शिक्षा अब आगनबाड़ी एवं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को बाल वाटिका के अंतर्गत कराई जाएगी उत्तराखंड प्रदेश में 20,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं इसमें से प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है इसके लिए पाठ्यक्रम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के द्वारा तैयार किया जा चुका है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के लिए हस्त पुस्तिका और बच्चों के लिए तीन अभ्यास पुस्तिकाएं जिसमें स्वास्थ्य ,संवाद एवं सृजन से संबंधित विषयों पर

*Corresponding Author: gbasera77@gmail.com

प्रकाश डाला गया है। सरकार के द्वारा शिक्षा नीति चलाने का निर्णय बेहतरीन है किंतु भौगोलिक परिस्थितियों, भौतिक संसाधनों,कुशल कार्यकताओं,विषय विशेषज्ञों की कमी के कारण उत्तराखंड में NEP 2020 चुनौती बना हुआ है।

प्रस्तावना

सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक विकास, राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, सतत प्रगतिशील और सहभागिता युक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण के लिए हमें एक ऐसा शैक्षणिक ढांचा खड़ा करना होगा जिससे युवा शिक्षित, प्रशिक्षित और नवाचारी हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड को सक्षम और आत्मनिर्भर तथा समर्थ बनाने हेतु नई शिक्षा नीति का पूर्ण रूप से लागू होना आवश्यक है क्योंकि विश्व में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। डाटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक तरफ विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी तो दूसरी तरफ डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, गणित, समाज विज्ञान और मानविकी में विशेष योग्यता रखने वाले प्रशिक्षित ऊर्जावान युवाओं की आवश्यकता होगी। महामारी और संक्रामक रोग प्रबंधन के लिए रिसर्च, रिसर्च सेंटर तथा विभिन्न सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए हमें समाज वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी जिसके लिए यह नीति महत्वपूर्ण साबित होगी।किसी भी देश, समाज और परिवार को विकसित, समृद्ध एवं प्रतिस्पद्ध बनाने के लिए शिक्षा को महत्व देना होगा। भारत में शिक्षा केन्द्र एवं राज्यों का विषय है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय हित में शिक्षा का मसौदा तैयार करती है, जिसका अनुमोदन संसद द्वारा लिया जाता है लेकिन राज्यों की विधान सभाओं को भी विचार विमर्श, बहस के माध्यम से अनुमति प्रदान करनी होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सहभागी बनाया गया है। जिसमें 2 लाख सुझावों का सहारा लिया गया है।देश में एक सी शिक्षा नीति के लक्ष्य को भी ध्यान में रखा गया है। उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को 2035 तक 26.3 प्रतिशत (वर्तमान में) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाना है। उच्च शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ती जा रही है। शिक्षा महंगी हो रही है। सरकारी शिक्षा में बजट कम हो रहा है, ऐसे में नई नीति किस तरह से देश एवं युवाओं के लिए मददगार होगी यह अभी भविष्य के गर्त में है।

शोध का उद्देश्य

1. नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानना ।

2. इस नीति के लक्ष्यों एवं सिद्धांतो का महत्व उत्तराखंड के परिपेक्ष्य में जानना।

3. उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 पुरानी शिक्षा नीति से किस प्रकार भिन्न है, इसको जानना।

4. उत्तराखंड में प्रचलित विद्यालयों में शिक्षा नीति 2020 में अभिभावकों,शिक्षकों , छात्रों हेतु नवाचार को जानना।

शोध विधि

यह लेख द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से लिखा गया है जिसमें अनेक समाचार पत्रों,लेखकों के लेखों,सरकारी गजट व सरकार द्वारा जारी आदेशों का अध्ययन किया है।

साहित्य समीक्षा

गंगवाल सुभाष 2020 ने लिखा है कि 21वीं सदी ज्ञान प्रधान सदी है जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी विकास परिवर्तन के प्रमुख आधार है।इस नीति का मसौदा निर्माण डॉ. कस्तुरी रंगन की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया गया है,इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया है बल्कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं व चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है।

प्रो. शर्मा के. एल. 2020 ने अपने लेखपत्र में लिखा है कि शिक्षा से सशक्त और सविमर्शी समाज बनाया जा सकता है लेकिन शिक्षा इतनी गुणवत्तापरक हो कि मनुष्य खुद को स्वतंत्र, रचनात्मक और नैतिक दृष्टि से दृढ़ समझ सके। शिक्षा परिवर्तन और सशक्तिकरण का साधन है। एस. राधाकृष्ण आयोग 1948. डी.एस. कोठारी आयोग 1964 प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अध्यापक राष्ट्रीय आयोग 1983. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 1999 और अनेक शिक्षा नीतियों के विचारों से बढ़कर क्या यह शिक्षा नीति है? अब तक कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा की दशा एवं दिशा की व्याख्या समावेशी मानी गई है। क्या वर्तमान शिक्षा नीति इससे भी व्यापक और गहन है? नीति आयोग के अनुसार नई नीति द्वारा प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली द्वारा नए भारत का निर्माण संभव होगा। नई नीति में प्रारम्भिक स्तर से उच्च स्तर तक संतुलित शिक्षा से सबको विकास का अवसर मिलेगा। परन्तु

नई शिक्षा नीति में शिक्षक और विद्यार्थी की दूषित स्थिति से निपटने पर यह नीति मौन है, इस पर किसी प्रकार की विवेचना का अभाव है।

सिंह दुर्गेश 2020 ने अपने लेख पत्र में लिखा है कि भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था त्रीस्तरीय है जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल है। यह शिक्षा व्यवस्था शिक्षित लेकिन रोजगार विहिन युवाओं को तैयार करती है। जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर के कुशल एवं दक्ष युवा तैयार करने में सक्षम नहीं है।

शिक्षा नीति 2020 का महत्व

नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है जिससे बच्चा बचपन से ही अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझ और जान पाएगा। इस नई नीति के तहत यदि कोई बच्चा अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पाने में असमर्थ है या 3 वर्ष का कोर्स पूरा नहीं कर पाता है तो भी उसका नुकसान नहीं होगा उसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा प्राप्त हो पाएगा। जिसका उपयोग वह रोजगार के क्षेत्र में कर पाएगा। छठी कक्षा से ही बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी जिससे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।शिक्षा नीति में कोडिंग को भी शामिल किया गया है, यानी बच्चे मात्र किताबी और व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं अपितु तकनीकी क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।कुल मिलाकर यह नीति बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगी। 2020 में नई शिक्षा नीति 30 वर्षों के बाद आई और भारत की मौजूदा शैक्षणिक प्रणाली को अकादमिक के अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर बनाने के उद्देश्य से बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2040 तक एनईपी की स्थापना करना है। लक्षित वर्ष तक, योजना का मुख्य बिंदु एक-एक करके लागू किया जाना है।एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित सुधार केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लागू होगा।यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत बनाए समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी | इस नीति में परिकल्पित है हमारे संस्थानों की पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि जो छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें ,इस नीति का विजन है छात्रों में, भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी रहे ; साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए | जो मानव अधिकार हो स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सकें।

शिक्षा नीति 2020 की उत्तराखंड में चुनौतियां

नई शिक्षा नीति -2020 (NEP2020) के माध्यम से शैक्षिक ढांचे को बेहतर बनाने का सरकार का प्रयास अपने आप में एक सराहनीय कार्य है, लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के तहत वर्णित किया जा सकता है:

• उत्तराखंड लगभग एक तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश बच्चे, जिनका स्कूल दूर है ,जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यकों और दिव्यांग समूहों से संबंधित हैं।

•उत्तराखंड राज्य पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में बंटा है जहां किसी क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं तो कहीं शीतकालीन। शिक्षा नीति से संबंधित सभी तथ्यों को एक साथ लागू करना टेड़ी खीर साबित हो सकता है।

•उत्तराखंड के अधिकांश प्राथमिक स्कूल एकल व दो शिक्षकों पर निर्भर हैं तो ऐसे में शिक्षा नीति को लागू करके उसका अपेक्षित परिणाम मिलना मुश्किल प्रतीत होता है।

•आज भले ही दुनियां चांद पर पहुंच गई किंतु उत्तराखंड के कई विद्यालय अभी भी नेटवर्क क्षेत्र,बिजली,पानी आदि सुविधाओं की बाट जोह रहा है ,ऐसे में नवाचारी , जिज्ञासु प्रवृत्ति छात्रों में कैसे जगा पाएंगे।

•उत्तराखंड राज्य के बुनियादी ढांचे की कमी से संबंधित है। यह आमतौर पर देखा गया है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय, चारदीवारी, पुस्तकालय, कंप्यूटर आदि की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणाली प्रभावित होती है।

• शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के विफल होने का ख़तरा है। इसका कारण शिक्षा नीति में बदलाव करते समय रोडमैप का पालन नहीं करना और नीतियों को बनाते समय सभी हितधारकों को ध्यान में नहीं रखना है।

• उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। उत्तराखंड में बहुतायत मात्रा में विश्वविद्यालय,महाविद्यालय,निजी स्कूल खुल रहे हैं जिसमें अप्रशिक्षित,अयोग्य लोगों के द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम हो रहा है।

• शिक्षा नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने से संबंधित सूत्र को लागू करना भी है। आज, दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में, अपने साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

- उत्तराखंड में शिक्षकों को शिक्षण के अलावा जनगणना वोटिंग जैसे अन्य कार्यों में भी सम्मिलित किया जाता है जिस कारण पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है और अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त करने में असफल रहते हैं
- आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील क्षेत्र है राज्य है जिससे समय-समय पर पढ़ाई प्रभावित होती है, NEP 2020 के अनुसार निर्धारित किए गए मानकों पर खरा उतरने के लिए उत्तराखंड में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है
- नीति 2020 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात उत्तराखंड बहुत पिछड़ा हुआ है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में छात्रों की संख्या बहुत कम है, लेकिन विद्यालय अत्यधिक दूर होने के कारण छात्र छात्राएं शिक्षा का लाभ लेने से वंचित रह जाती है।

• मसौदे में त्रिभाषी नीति भी NEP2020 के सामने एक चुनौती पेश कर रही है, जिसमें गैर-हिंदी भाषा क्षेत्रों में मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी को तीसरी भाषा बनाने की सिफारिश की गई है। तीन भाषा सूत्र नया नहीं है और पिछली शिक्षा नीतियों में, 1968 और 1986 में इसकी पहले से ही सिफारिश की गई थी किंतु उनका अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त नहीं हुए। वास्तव में NEP2020 सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियाँ भी हैं। उल्लेखनीय है कि इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास पूर्व में भी किया जा चुका है, लेकिन उपलब्धियाँ सराहनीय नहीं रही हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

इस नीति के तहत, शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार, नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, विशेषज्ञों, अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों को अपने स्तर पर काम करना चाहिए। शैक्षिक संस्थान, कार्यान्वयन एजेंसियों, छात्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के नेताओं के बीच एक सहजीवी संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए, नवाचारों का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकता है जिसमें रोज़गार के बड़े अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि उद्योग शिक्षण संस्थानों से जुड़े हो। इसके अलावा, कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों को विशेष महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और देश के

डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टोरल प्रोग्रामों के अनुसंधान के लिए वित्त प्रदान करना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, प्रतिष्ठित उद्योग संगठनों, मीडिया हाउस और पेशेवर निकायों को भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को रेटिंग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक मजबूत रेटिंग प्रणाली विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी और उनके प्रदर्शन में सुधार करेगी। उत्तराखंड का विश्वविद्यालय अभी भी दुनिया के शीर्ष 500 रैंक वाले विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं हैं। इस संबंध में, विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों को संबंधित मानकों में आत्मनिरीक्षण और सुधार करना चाहिए। स्कूली शिक्षा में सुधार के अलावा, शिक्षण और प्रशिक्षण विधियों में भी सुधार किया जाना चाहिए,एक ओर, संस्थान की स्वायत्तता की वकालत की जाती है, जबकि दूसरी ओर, मौजूदा व्यवस्था में, यदि आप विश्वविद्यालय के भीतर एक संगोष्ठी तक आयोजित करना चाहते हैं, तो आपको कुलपति से अनुमति लेनी होगी। एक और उदाहरण में, एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की जाती है और दूसरी तरफ देश की सरकार के मंत्री ऐसे भाषण देते हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह, इस NEP2020 का वक्तव्य बहुत अच्छा है, बशर्ते यह वास्तव में लागू हो। यदि सरकार इसे अपनी भावना और मन में लाये और इसके आधार पर, मूल ढांचे को बदलने के इरादे से पूरी शैक्षिक संरचना पर काम करे तभी कुछ संभव है। सिर्फ अच्छे शब्दों से काम नहीं चलेगा। इसके क्रियान्वयन पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें आने वाले दशकों में यह भी देखना होगा कि सरकारें NEP2020 के अनुसार क़ानूनों को बदलने के बाद आवश्यक अतिरिक्त बजट प्रदान करने और उसे खर्च करने में सक्षम है या नहीं।

संदर्भ सूची

1) Nandini, ed. (29 July 2020). "New Education Policy 2020 Highlights: School and higher education to see major changes". Hindustan Times. Archived from the original on 30 July 2020. Retrieved 30 July 2020.
2) Jebaraj, Priscilla (2 August 2020). "The Hindu Explains | What has the National Education Policy 2020 proposed?". The Hindu. ISSN 0971-751X. Archived from the original on 2 August 2020. Retrieved 2 August 2020.
3) Vishnoi, Anubhuti (31 July 2020). "No switch in instruction medium from English to regional languages with NEP '20: HRD". The Economic Times. Archived from the original on 15 July 2021. Retrieved 31 July 2020.

4) Gohain, Manash Pratim (31 July 2020). "NEP language policy broad guideline: Government". The Times of India. Archived from the original on 31 July 2020. Retrieved 31 July 2020.
5) Chopra, Ritika (2 August 2020). "Explained: Reading the new National Education Policy 2020". The Indian Express. Archived from the original on 1 August 2020. Retrieved 2 August 2020.
6) "Education in Mother Tongue". www.pib.gov.in. Archived from the original on 23 January 2023. Retrieved 23 January 2023.
7) "মমালংান্দা লাইরকি তম্বা". pib.gov.in (in Manipuri). Archived from the original on 23 January 2023. Retrieved 23 January 2023.
8) Chaturvedi, Amit (30 July 2020). "'Transformative': Leaders, academicians welcome National Education Policy". Hindustan Times. Archived from the original on 31 July 2020. Retrieved 30 July 2020. While the last policy was announced in 1992, it was essentially a rehash of a 1986 one.
9) "Kasturirangan-led panel to develop new curriculum for schools". indianexpress.com. 22 September 2021. Archived from the original on 16 October 2021. Retrieved 16 October 2021.
10)"State education boards to be regulated by national body: Draft NEP". The Times of India. 30 October 2019. Archived from the original on 27 February 2021. Retrieved 21 November 2019.
11)"Here's Why You Can Rejoice Over the New NEP. And Why You Cannot". The Wire. 31 July 2020. Archived from the original on 1 August 2020. Retrieved 2 August 2020.
12)Jebaraj, Priscilla; Hebbar, Nistula (31 July 2020). "Rigorous consultations done before framing new National Education Policy, says Ramesh Pokhriyal Nishank". The Hindu. ISSN 0971-751X. Archived from the original on 6 August 2020. Retrieved 2 August 2020.
13)Rohatgi, Anubha, ed. (7 August 2020). "Highlights | NEP will play role in reducing gap between research and education in India: PM Modi". Hindustan Times. Archived from the original on 9 August 2020. Retrieved 8 August 2020.

14)"Govt approves plan to boost state spending on education to 6% of GDP". Livemint. 29 July 2020. Archived from the original on 8 August 2020. Retrieved 30 July 2020.

15)"National Education Policy 2020: Cabinet approves new national education policy: Key points". The Times of India. 29 July 2020. Archived from the original on 29 July 2020. Retrieved 29 July 2020.

16)"Teaching In Mother Tongue Till Class 5: 10 Points On New National Education Policy". NDTV.com. Archived from the original on 30 July 2020. Retrieved 30 July 2021.

17)"Cabinet Approves National Education Policy 2020, paving way for transformational reforms in school and higher education systems in the country". pib.gov.in. Archived from the original on 8 August 2021. Retrieved 8 August 2021.

18)https://en.m.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020

19)https://www.drishtiias.com/hindi/state-pcs-current-affairs/new-education-policy-2020-implemented-in-uttarakhand

20)https://truestory.co.in/?p=3789

21)https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-editorials/an-education-policy-that-is-sweeping-in-its-vision

22)https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

23) https://kisansuchna.com/nai-rashtriya-shiksha-niti-2020/

24) https://kisansuchna.com/nai-rashtriya-shiksha-niti-2020/